

## पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 'छात्रावास निर्माण योजना' के अन्तर्गत 06 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण

ओबीसी छात्र-छात्राओं को शीघ्र ही शैक्षिक आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी

लखनऊ : 25 जून, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास निर्माण एवं छात्रावास अनुरक्षण योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को उच्च गुणवत्ता युक्त सुरक्षित, सुविधाजनक एवं अनुकूल शैक्षिक आवासीय वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्त सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 20 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गयी है। योजनान्तर्गत राजकीय शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं के छात्रावास हेतु केंद्र व राज्य का अनुपात 90:10 तथा छात्रों के छात्रावास हेतु 60:40 अनुपात निर्धारित किया गया है। इसमें कुल 33 प्रतिशत छात्रावासों का निर्माण छात्राओं के लिए आरक्षित है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक कुल 102 छात्रावासों का निर्माण कराया जा चुका है, जिनमें 59 छात्रों हेतु और 43 छात्राओं के लिए, जिनकी कुल क्षमता 5400 की है। विगत वर्ष 2013 छात्र-छात्राओं द्वारा इसका लाभ उठाया गया।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक में माओ मंत्री जी को बताया गया कि राजकीय पॉलिटेक्निक, हण्डिया (प्रयागराज), राजकीय के.जी.के. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज (मुरादाबाद), काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर (संत रविदास नगर), सर्वोदय इंटर कॉलेज, मिहीपुरवा (बहराइच), लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय (गोण्डा), वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (महोबा) में निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

राजकीय इंटर कॉलेज (हमीरपुर) में निर्माण कार्य 90 प्रतिशत, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक (लखनऊ) का निर्माण कार्य 85 प्रतिशत और फैज-ए-आम इंटर कॉलेज (मेरठ) का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, जिसको जुलाई 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री कश्यप ने बताया कि उ0प्र0 सरकार ने पूर्व में निर्मित छात्रावासों के रख-रखाव एवं मरम्मत की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 'छात्रावास अनुरक्षण योजना' वर्ष 2023-24 से आरम्भ की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 05 करोड़ रुपये बजट का प्राविधान किया गया है। उन्होंने विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी निर्माण और अनुरक्षण कार्यों की निरंतर और नियमित मॉनीटरिंग करें साथ ही निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य गुणवत्ता व मानक के अनुरूप पूर्ण कराने को सुनिश्चित करें ताकि छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। निर्माण व अनुरक्षण कार्य में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता के साथ समझौता न किया जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा छात्रावास संबंधी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

---

सम्पर्क सूत्र- मो0 इकबाल खॉ

राघवेन्द्र / 06:15 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं0 : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : [upssochna@gmail.com](mailto:upssochna@gmail.com),

वेबसाइट : [www.information.up.gov.in](http://www.information.up.gov.in)